बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 59 ● नई दिल्ली ● वीरवार 11 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

लाल किला में शाहजहां की वापसी, फिर सुर्खियों में आया एअर इंडिया का ये खास विमान

नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इन दिनों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए लाल किले में शाहजहां की भव्य वापसी हुई है,जो दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि यहां बात उस महान मुगल बादशाह शाहजहां की नहीं, बल्कि एक शानदार पुराने विमान की हो रही है,बोइंग 747 जंबो जेट का एक आकर्षक मॉडल, जिसका नाम शाहजहां रखा गया था। यह विमान कभी एअर इंडिया के प्रसिद्ध एम्परर (सम्राट) बेड़े का हिस्सा था। यह विशाल विमान मॉडल अब लाल किले के अंदर ब्रिटिश काल के एक बैरक के सामने गर्व से खड़ा है।

लोकसभा में चुनाव सुधार पर तीखी बहस, सीजेआई को सीईसी के चयन पैनल से हटाने पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

नई दिल्ली ।

लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर उस समय जोरदार बहस छिड़ गई जब कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाए जाने पर अपनी-अपनी दलीलें रखीं। दोनों दलों ने इस मुद्दे पर अपनी ठोस राय सामने रखकर सदन का माहौल गरम कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा कि आखिर वह सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था से पीछे क्यों हट गई, जिसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अंतिम बिल में सीजेआई को बाहर क्यों रखा गया। इसके तुरंत बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया और सरकार के फैसले का बचाव किया।

कांग्रेस ने सीजेआई को हटाए जाने पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसका नेतृत्व अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. एम. जोसेफ कर रहे थे, ने स्पष्ट किया था कि जब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई व्यापक कानून नहीं बन जाता, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाए। लेकिन जब सरकार बिल

लेकर आई, तो उसने सीजेआई को पूरी तरह बाहर कर दिया और उसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। उन्होंने मांग की कि कानून मंत्री इस फैसले पर स्पष्ट जवाब दें।

भाजपा ने किया पलटवार

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जब देश की जनता प्रधानमंत्री को परमाणु बटन तक संभालने का भरोसा देती है, तो वही प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली सरकार एक ईमानदार और सक्षम चुनाव आयुक्त क्यों नहीं चुन सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, और हर कार्य में न्यायपालिका को शामिल करने की मांग तर्कसंगत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि स्वयं वेणुगोपाल भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह प्रावधान सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था थी, स्थायी समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि संसद ने व्यापक विचार के बाद नया कानून पारित किया है और इसके बाद भी सीजेआई को पैनल में शामिल रखने की मांग राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चयन प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर जरूरी सुधारों को बाधित करना चाहती है।

पहले ही ये बिल हो चुका पेश

सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को संसद पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे। लेकिन सीजेआई को शामिल न किए जाने से विपक्ष को तीखा विरोध करने का मौका मिला है। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा, जबकि भाजपा दावा करती है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है।

रोहिंग्या पर ऐसा क्या बोल गए सीजेआई सूर्यकांत, बनने लगे निशाना, समर्थन में आए 44 रिटायर्ड जज

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 44 पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या प्रवासी मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ चलाए जा रहे सोची-समझी साजिश की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि आलोचकों ने एक सामान्य कानूनी प्रश्न को पूर्वाग्रह के आरोपों में तब्दील कर दिया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि सामान्य न्यायिक प्रश्नों को पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियों के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का उद्देश्य न्यायपालिका को कमजोर करना और संवैधानिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करना है।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यद्यपि न्यायिक निर्णयों और अदालत में होने वाली चर्चाओं की निष्पक्ष और जानकारीपूर्ण आलोचना की जा सकती है, लेकिन वर्तमान विवाद इस सीमा को पार कर गया है। न्यायिक कार्यवाहियाँ निष्पक्ष और तर्कपूर्ण आलोचना के अधीन हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। हालाँकि, हम जो देख रहे हैं, वह सैद्धांतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक नियमित अदालती कार्यवाही को पूर्वाग्रह से प्रेरित कृत्य बताकर न्यायपालिका को अवैध ठहराने का प्रयास है। मुख्य न्यायाधीश पर सबसे बुनियादी कानूनी सवाल पूछने के लिए हमला किया जा रहा है कानूनन, न्यायालय के समक्ष जिस दर्जे का दावा किया जा रहा है, वह दर्जा किसने दिया है? अधिकारों या हकों पर कोई भी निर्णय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि इस सीमा को पहले संबोधित नहीं किया जाता, बयान में कहा गया है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि आलोचकों ने न्यायालय की गलत व्याख्या की है, और सभी के सम्मान और सुरक्षा के उसके संदेश की अनदेखी की है। इसी तरह, यह अभियान सुविधाजनक रूप से पीठ की इस स्पष्ट पुष्टि को नज़रअंदाज़ कर देता है कि भारतीय धरती पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को यातना, गुमशुदगी या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं बनाया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

इसे दबाना और फिर न्यायालय पर अमानवीयकरण का आरोप लगाना, वास्तव में कही गई बात का गंभीर रूप से विरूपण है।

राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को बीजेपी ने बताया भारत बदनामी टूर, कहा- सदन में रहेंगे तभी बोलेंगे, विदेश घूमेंगे तो कैसे?

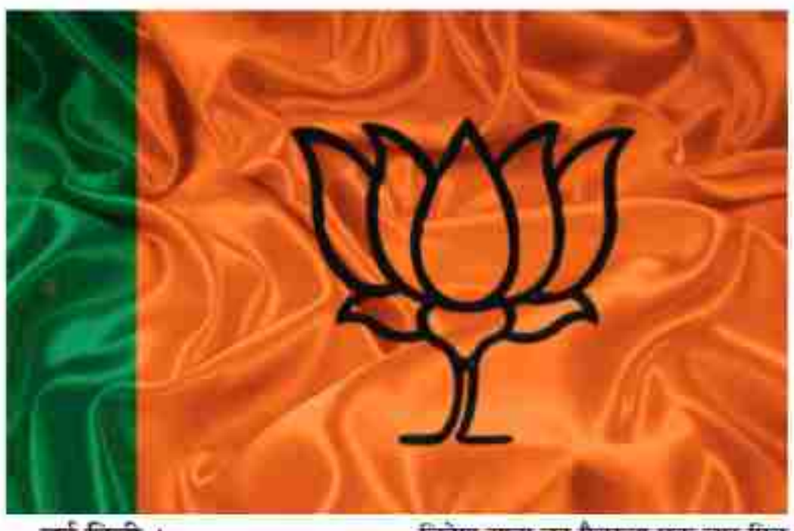

नई दिल्ली ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इसे भारत बदनामी यात्रा बताया है और कांग्रेस नेता पर विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करने का आरोप लगाया है। शीतकालीन संसद का सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, ऐसे में पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी का विदेश यात्रा का फैसला एक बार फिर उनकी स्पष्ट प्राथमिकताओं को दर्शाता है।गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहाँ वे यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मिलेंगे। तीखा प्रहार करते हुए पूनावाला ने एएनआई से कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विपक्ष का नेता का मतलब पर्यटन का नेता होता है। वह एक गैर-गंभीर राजनेता हैं। लोग काम के मूड में हैं, जबकि वह छुट्टी के मूड में हैं - हमेशा के लिए छुट्टी के मूड में। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी अक्सर विदेश चले जाते हैं, और याद दिलाया कि बिहार चुनावों के दौरान, जब दूसरे लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब वे जंगल सफारी पर थे। जर्मनी यात्रा के पीछे के इरादे के बारे में बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे किसी कारण से क्यों जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे भारत के खिलाफ जहर उगलना चाहते हों। यह भारत बदनामी ब्रिगेड और भारत बदनामी टूर है। पूनावाला ने लिखा कि विदेश नायक एक बार फिर वही कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं! विदेश यात्रा पर जा रहे हैं! संसद 19 दिसंबर तक है, लेकिन खबरों के अनुसार राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे! राहुल विपक्ष के नेता हैं - विदेश के नेता। बिहार चुनावों के दौरान भी वे विदेश में थे और फिर जंगल सफारी पर गए थे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनावों के दौरान भी इसी तरह विदेश में थे। बिहार चुनावों के दौरान भी वे विदेश में थे और फिर जंगल सफारी पर गए थे।

मैं नहीं जाऊंगा : वीर सावरकर के नाम वाला सम्मान लेने पर शशि थरूर, बोले- ये आयोजकों की गैरजिम्मेदाराना हरकतं

नई दिल्ली । वीर सावरकर पुरस्कार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान थरूर ने कहा कि उन्होंने यह पुरस्कार कल ही (मंगलवार) के दिन सुना और वे पुरस्कार समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में कल ही सुना। मैं वहां नहीं जा रहा हूं। शशि थरूर ने साफ किया कि वह वी.डी. सावरकर के नाम पर दिया जाने वाला कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इससे जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने यह भी कहा कि मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना आयोजकों की ओर से गैरजिम्मेदाराना हरकत थी। थरूर के बयान के बाद पुरस्कार देने वाली हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया के सचिव अजी कृष्णन ने एक टीवी चैनल को बताया कि कांग्रेस सांसद को इस मामले की जानकारी काफी पहले ही दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि एचआरडीएस इंडिया के प्रतिनिधियों और पुरस्कार जूरी के अध्यक्ष ने थरूर को आमंत्रित करने के लिए उनके आवास पर उनसे मुलाकात की थी और सांसद ने पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं की सूची मांगी थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा, हमने उन्हें सूची दे दी थी। उन्होंने अभी तक हमें सूचित नहीं किया है कि वे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शायद वे डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने कहा, पुरस्कार की प्रकृति, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में, आज कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने के लिए केरल जाने पर उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

दूसरी ओर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने बुधवार को इस मामले में कहा कि किसी भी कांग्रेस सदस्य को चाहे वह सांसद शशि थरूर ही क्यों न हों वीर सावरकर के नाम का कोई भी पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। मुरलीधरन ने इसका कारण बताया कि सावरकर ने ब्रिटिशों के सामने झुकाव दिखाया था। मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शशि थरूर यह पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना कांग्रेस पार्टी के लिए अपमान और शर्मिंदगी का कारण बन सकता है।

दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल, बच्चों की छुट्टी कराकर जांच में जुटीं टीमें

नई दिल्ली। राजधानी में दो स्कूलों को दिन में पहले बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलने के बाद, बुधवार को संस्कृति स्कूल को भी इसी तरह का एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें खालिस्तान आंदोलन का जिक्र था। संदेश में लिखा था, आज दोपहर 12:05 बजे बम धमाका होगा? झूठी पुलिस मुकाबला करके पंजाब में खालिस्तान जनमत संग्रह करवा दें; खालिस्तान आंदोलन को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र तक ले आएं। अधिकारी इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आज सुबह, स्कूलों ने एहतियात के तौर पर अभिभावकों को अपने बच्चों को लेने के लिए तुरंत एक सूचना जारी की। सूचना में छात्रों और अभिभावकों के बीच घबराहट पैदा किए बिना स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और उसे संभालने के लिए छात्रों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल भेजने की प्रक्रिया बताई गई। द इंडियन स्कूल द्वारा जारी नोटिस में लिखा था, प्रिय अभिभावकगण, स्कूल को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर, स्कूल बच्चों को छुट्टी दे रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए समय के अनुसार अपने बच्चे को लेने आएं- नर्सरी से कक्षा 2 से सुबह 9:30 बजे, कक्षा 3 से : सुबह 9:45 बजे, कक्षा 6 से 8:सुबह 9:55 बजे, कक्षा 9 और उससे ऊपर- सुबह 10:15 बजे। इसी समय, नई दिल्ली स्थित अहलकोन इंटरनेशनल स्कूल को भी बम की धमकी मिली। स्कूल ने भी अभिभावकों को इसी तरह का एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें छात्रों को सुरक्षित और समय पर ले जाने के लिए वैन चालकों के साथ समन्वय करने की सलाह दी गई। नोटिस में कहा गया कि प्रिय अभिभावक, कृपया ध्यान दें कि आज सुबह प्राप्त एक ईमेल धमकी के कारण, हम अपने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सभी छात्रों (फुटबोर्ड/बस/वैन) के लिए सुबह 11:30 बजे जल्दी स्कूल छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं।

गोवा क्लब अग्निकांड : गौरव-सौरभ लूथरा ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, कोर्ट को बताया- वह क्लब के मालिक नहीं

नई दिल्ली । गोवा क्लब अग्निकांड मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जहां आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने भारत लौटने और इस मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए अर्जी दी है। दोनों आरोपियों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर पेश हुए और अंतरिम सुरक्षा की मांग की। सुनवाई के दौरान, आरोपी सौरभ लूथरा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए आरोपी सौरभ लूथरा की सेहत की स्थिति बताई, जिसे मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी क्लब के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ लाइसेंसधारी हैं, जो वैध परमिशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि मालिकाना हक किसी और के पास है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोवा नाइट क्लब आग मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शारीरिक तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में मौजूद नहीं है, कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत की याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जवाब में लूथरा भाईयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए कानूनी मिसालों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह यह एप्लीकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का स्थायी निवासी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ गिरफ्तारी से सुरक्षा मांग रहे हैं। हालांकि राज्य के वकील ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि आरोपी देश छोड़कर भाग गया है, गोवा कोर्ट ने पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुका है और अन्य जरूरी तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य को सभी जरूरी सूचनाओं के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगले दिन विचार करने के लिए तारीख तय की। आरोपियों के वकील ने तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट से अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा देने का आग्रह किया। राय के वकील ने इस अनुरोध का विरोध किया और किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने का कड़ा विरोध किया।

भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट- भ्रष्टाचार की मिलीभगत की संरचनात्मक भूमिका

वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से शहरी विकास,बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनसंख्या की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के दौर से गुजर रहा है,जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 780 जिलों में विशाल संख्या में मॉल,मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट,नाइट क्लब, सिनेमाहॉल,सुपर बाजार,कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन केंद्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों-लाखों नागरिक आते हैं, जो आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसी विकास की यात्रा के भीतर एक गंभीर प्रश्न भी मौजूद है,भ्रष्टाचार,गैर-जवाबदेही, फायर-सेफ्टी की अनदेखी और प्रशासनिक निरीक्षण की कमी, जो कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं।मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में लगी भयंकर आग, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई, इस समस्या का चरम उदाहरण है।इस हादसे ने यह उजागर कर दिया कि देश के अनेक जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान सक्रिय हैं, जिनके पास न तो वैध फायर-सेफ्टी प्रमाणपत्र है,न बिल्डिंग बायलॉज की स्वीकृति, न ही नगर परिषद/महानगर पालिका/राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं है,बल्कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें, लाइसेंसों की अवैध खरीद-फरोख्त,और निरीक्षण एजेंसियों की मिलीभगत का दुष्परिणाम है। जिस प्रकार गोवा के नाइट क्लब को बिना उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलने दिया गया,उसी प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन आम हो चुका है, जिसे रोकने के लिए अब कलेक्टर-स्तर पर सख्त संज्ञान आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। साथियों बात अगर हम भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा संकट और भ्रष्टाचार की संस्थागत भूमिका को समझने की करें तो, भारत में एक ओर अत्याधुनिक मॉल, कैफे, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन केंद्र शहरों की पहचान बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थिति भयावह रूप से कमजोर पाई जाती है। कई जिलों में यह पाया गया है कि (1) फायर-सेफ्टी ऑडिट वर्षों तक नहीं हुए, (2) आपातकालीन निकास अवरुद्ध है, (3)फायर-अलार्म और स्प्रिंकलर कार्यरत नहीं (4) बिल्डिंग बायलॉज का पालन न्यूनतम, (5)ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग,(6)अवैध निर्माण और अवैध विस्तार,(7) बिना अनुमति नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट और कोचिंग केंद्र संचालन, (8)और सबसे चिंताजनक-भ्रष्टाचार के चलते फर्जी लाइसेंस जारी करना।भारतीय नगर प्रशासन या स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार नई बात नहीं है, लेकिन जब यह भ्रष्टाचार नागरिक जीवन के मूलभूत अधिकार, सुरक्षित वातावरण को खतरे में डाल दे, तब यह केवल नैतिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता,बल्कि नरसंहार जैसी परिस्थितियों का जन्म देने वाली संस्थागत विफलता बन जाता है।गोवा की घटना हो या दिल्ली के मुंडका फायर हादसा, मुंबई का कमला मिल फायर, सूरत का कोचिंग सेंटर मामला,हर घटना के पीछे एक समान कारण दिखाई देता है,भ्रष्टाचार के बदले मिले फर्जी प्रमाणपत्र और नियमों के क्रियान्वयन में गहरी प्रशासनिक उदासीनता।भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, फायर सेवा अधिनियम, नगर पालिका और राष्ट्रीय भवन संहिता जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इन कानूनों के पालन की जिम्मेदारी संभालने वाला निकाय-भ्रष्ट प्रशासन ही भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्थाएं केवल कागजी बनकर रह जाती हैं। इसलिए यह मॉडल अब अप्रभावी माना जा रहा है और आवश्यक है कि निरीक्षण का अधिकार सीधे जिलाधिकारी /कलेक्टर के हाथों में आए, जो जिले का सर्वोच्च कार्यपालिक अधिकारी होता है और भ्रष्टाचार- रोधी शक्तियां भी रखता है। साथियों बात अगर हम कलेक्टर द्वारा संज्ञान आधारित आकस्मिक निरीक्षण की अनिवार्यता को समझने की करें तो,प्रत्येक जिले में कलेक्टर स्वयं आकस्मिक निरीक्षण करें,यह वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अत्यंत व्यवहारिक, प्रभावी और नागरिक-हितकारी समाधान है। इसका कारण स्पष्ट है (1) कलेक्टर भ्रष्टाचार-रोधी शक्तियों से लैस होता है।(2) स्थानीय निकाय, नगर परिषद या निगम पर होने वाले राजनीतिक दबाव का प्रभाव कलेक्टर पर कम पड़ता है। (3) स्वत संज्ञान लेने की शक्ति के कारण कलेक्टर किसी भी संस्था पर तात्कालिक जांच और कार्रवाई कर सकता है। (4) आकस्मिक निरीक्षण भ्रष्टाचार की पैठ तोड़ने वाला सबसे प्रभावी उपाय है।(5) कलेक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी से स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही स्वत- बढ़ जाती है।देश में अक्सर देखा गया है कि फायर सेवा विभाग, नगर निगम या लाइसेंसिंग अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमों के उल्लंघन के बावजूद 'क्लीन चिट' दे देते हैं। ऐसे में यदि कलेक्टर हर जिले में-मॉल, होटल,नाइट क्लब,बड़े रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स सुपर बाजार,स्कूल/कॉलेज,कोचिंग सेंटर,और अन्य भीड़- भरकत वाली इमारतों का स्वत- संज्ञान लेकर निरीक्षण करें, तो नागरिक सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। कलेक्टर- स्तरीय निरीक्षण से यह भी सुनिश्चित होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों और असुरक्षित प्रतिष्ठानों की तुरंत पहचान की जाए, और उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। गोवा हादसा इसी बात का प्रमाण है कि यदि जिला प्रशासन सक्रिय रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों पर समय- समय पर निगरानी करता, तो शायद 25 निर्दोष नागरिकों की जान बच सकती थी। साथियों बात अगर हम भीड़- उपस्थितियों वाले संस्थानों पर अनिवार्य नियमित निरीक्षण एक नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता इसको समझने की करें तो, प्रत्येक जिले में सभी ऐसे संस्थानों पर जहां बड़ी संख्या में आम जनता एकत्रित होती है, नियमित निरीक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यह निरीक्षण त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक न होकर व्यवसाय के प्रकार, भीड़ की मात्रा, जोखिम स्तर और भवन संरचना के आधार पर होना चाहिए।उदाहरण के लिए,नाइट क्लब, बार, बेसमेंट रेस्टोरेंट मासिक निरीक्षण,मल्टीप्लेक्स, मॉल, भीड़भाड़ बाजार हर तीन माह में निरीक्षण,स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सत्रारंभ से पहले अनिवार्य निरीक्षण होटल और गेस्टहाउस प्रत्येक छह माह में निरीक्षण इन निरीक्षणों में निम्न बिंदुओं की सुनिश्चितता आवश्यक है (1) फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता (2) आपातकालीन निकास मार्ग (3)भीड़ नियंत्रण तकनीक (4) इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सुरक्षा(5) एलपीजी/गैस सुरक्षा(6) बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन (7) सुरक्षा कर्मियों की प्रशिक्षित टीम(8) सीसीटीवी और निगरानी प्रणाली,भारत में कई हादसों की मुख्य वजह यह रही है कि ऐसे निरीक्षण या तो कभी हुए ही नहीं, या निरीक्षण रिपोर्ट भ्रष्टाचार के कारण कागज़ पर पास दिखाई गई। इसलिए, कलेक्टर-स्तरीय निगरानी के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इन्स्पेक्शन रजिस्टर की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए ताकि जनता खुद जांच सके कि उनके जिले के प्रतिष्ठानों ने कौन-कौन से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। साथियों बात अगर हम सुरक्षा निरीक्षण के पालन की सार्वजनिक घोषणा इंडिया सेफ्टी चार्ट का अनिवार्य प्रदर्शन इसको समझने की करें तो,विश्व के कई देशों में, जैसे सिंगापुर, जापान, कनाडा और जर्मनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक पब्लिक सेफ्टी चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाने का समय आ चुका है।इसे भारत सुरक्षा चार्ट / इंडिया सेफ्टी कम्प्लायंस चार्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए- (1)अंतिम फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र की तिथि (2) बिल्डिंग बायलॉज अनुपालन स्तर (3) इमरजेंसी निकास योजना(4)अग्निशमन उपकरणों की क्षमता व स्थिति (5) अधिनियमों के अंतर्गत उठाए गए सुरक्षा कदम (6)स्वच्छता और विद्युत सुरक्षा जांच की तिथि (7) कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी का डिजिटल सत्यापन, इस चार्ट को रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, थिएटर, संस्थानों व नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, ताकि नागरिक स्वयं जान सकें कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। यदि कोई प्रतिष्ठान इस चार्ट को प्रदर्शित नहीं करता, तो उसे स्वत नोटिस-श्रेणी में रखा जाए और कलेक्टर कार्रवाई करें। साथियों बात अगर हम लाइसेंस उल्लंघन, अवैध संचालन और गैर-अनुपालन पर कठोर कार्रवाई इसको समझने की करें तो ,बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाए। एक व्यावसायिक और नागरिक- अधिकार आधारित मांग है। भारत में कई बार देखा गया है कि अवैध ढंग से संचालित प्रतिष्ठान- (1)राजनीतिक संरक्षण, (2)पुलिस/नगर निकाय भ्रष्टाचार,(3)या सिस्टम की ढिलाई, के कारण वर्षों तक चलते रहते हैं। जबकि वे हजारों लोगों की जान खतरे में डालते हैं। यदि कलेक्टर स्तर पर निम्न नीतियां लागू की जाएं-(1)पहली बार में 10 लाख तक का जुर्माना-15 दिन का निलंबन (2) दूसरी बार में लाइसेंस का स्थायी रद्दीकरण(3)तीसरी बार में आपराधिक मुकदमा (आईपीसी 304, 336, 337, 338 के तहत) तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।नियमों का उल्लंघन केवल प्रशासनिक गलती नहीं है,यह सीधे-सीधे नागरिक जीवन को खतरे में डालने की मानसिकता है, जो गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

सम्पादकीय...

कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय

एक के बाद एक चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी हताश हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर 1885 को हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान पर रही। कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास जानने वाले आज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, ए.ओ. ह्यूम, पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी की कांग्रेस को वर्तमान में क्या हो गया है। कांग्रेस देशभर में क्यों सिमटती जा रही है। देश में लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो लेकिन इस समय विपक्ष पूरी तरह से हाशिये पर है। राजनीति का इतिहास बताता है कि समय-समय पर विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और उसे सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष भी किया। इनमें राम मनोहर लोहिया का नाम अग्रणी रहा जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा जय प्रकाश नारायण ने सन् 1974 में इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फैंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इमरजैंसी के बाद देश में ऐसी जनक्रांति हुई कि जनता पार्टी ने 1977 में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित कर दिया लेकिन 19 महीने बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई और सत्ता में आ गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स दलाली कांड को लेकर राजीव गांधी को सत्ता से हटाया था। राजीव गांधी की शहादत के बाद कांग्रेस फिर पुन जीवित हुई और सत्ता में आई। 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार हुआ और एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान डालने के लिए लगातार मेहनत की। एक के बाद एक मुद्दे उठाए लेकिन उनका राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। 2017 में उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था जो उनकी राजनीतिक महत्वकांक्षा का चरम था। उन्होंने 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 2024 में भारत न्याय यात्रा निकाली थी। जिनमें उन्होंने देशमें एकता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उजागर किया था। राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जन केन्द्रित पहल रही। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी दिखा। उनकी कमजोर छवि और वंशवाद के आरोपों ने उनकी लोकप्रियता को प्रभावित किया। वे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आलोचक उन्हें निर्णय न लेने वाला अनिच्छित और कमजोर नेता मानते हैं। लगातार चुनावी हार के चलते पार्टी के भीतर भी उनके विरोध में स्वर सुनाई देते हैं। यह विडम्बना ही है कि वे खुद को देशकी जनता में विश्वसनीय रिश्ते कायम करने में विफल रहे हैं। राजनीति के विशेषज्ञ बार-बार यह कहते हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है तो जिन लोगों ने भी लोकसभा में वंदे मातरम् के सृजन के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान उनके संबोधन को सुना, वे यह स्वीकार करते हैं कि वे भाषण देने में अधिक सहज और साफ हैं। हिन्दी बोलने पर उनका अच्छी दक्षता है। उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से एक-एक बार पलटवार किया। वह अपनी दादी इंदिरा गांधी की ही तरह लोगों से तुरंत रिश्ता जोड़ लेती हैं और हंसते-हंसते अपनी बात को सहज ढंग से पहुंचाने में पारंगत हैं। प्रियंका का व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है। प्रियंका के अब तक के राजनीतिक सफर को आलोचक भले ही सफल न मानते हों लेकिन वह पार्टी में जान फूंकने के लिए ज्यादा सक्षम दिखाई दे रही हैं। वह कांग्रेस के जुझारू नेता के रूप में उभर चुकी हैं। साल 2019 में इच्छा न होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी जी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने आम और विधानसभा दोनों चुनावों में अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस भागीदारी ने उन्हें इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समर्थन के साथ एक जानी-मानी हस्ती बना दिया। इसकी वजह से संविधान में चुनाव के दौरान 'अमेठी का डंका, बिटिया प्रियंका' के जबरदस्त नारे लगे थे। वहीं, अक्तूबर 2021 में यूपी पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया था। पहली बार डेस्टिनेशन वेस्टर्न यूपी के सिद्धार्थ खेड़ी की उनकी यात्रा के बाद हुई, जहां रैली के बाद 8 लोग मारे गए थे। उन्हें और कई अन्य पार्टी के नेताओं को एक गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर रखा गया था, जहां उन्हें अस्थायी जेल के रूप में रखने के लिए 50 घंटे से अधिक समय तक रखा गया था। आगरा जाते समय उन्हें पुलिस ने रोका तो भी प्रियंका ने सभा की थी। प्रियंका गांधी की जिन्दगी का एक अनोखा पन्ना और है। यह राजीव गांधी की हत्यारिन नलिनी मुरगन के प्रति उनका सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। प्रियंका उससे वेल्लूर जेल में जा कर मिली थी। नलिनी जिसको फांसी लगनी थी, की एक छोटी बेटी भी थी। प्रियंका के सुझाव पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के. आर. नारायणन को पत्र लिखा था कि -न मैं और न ही मेरे बच्चे राहुल और प्रियंका चाहते हैं कि एक और जिन्दगी को बुझा दिया जाए। उसकी छोटी बेटी है। मेरे बच्चों ने भी पिता खोया था। कोई भी बच्चा हमारे कारण अनाथ नहीं बनना चाहिए- इसलिए हमारी अपील है कि उसे फांसी के फंदे से बचा लिया जाए। उसी के बाद नलिनी की किस्मत बदल गई और वह फांसी से बच गई और 31 साल के बाद वह जेल से बाहर आ गई। नलिनी की रिहाई में प्रियंका गांधी ने असाधारण इंसानियत का परिचय दिया। सोनिया गांधी पर लिखी किताब 'द रेड साड़ी' में लेखक जेवियर मोरो ने प्रियंका गांधी के बारे में लिखा था कि वह इंदिरा गांधी जैसी लगती है। वही चाल-ढाल और वही चमकती आंखें। राजनीति में चुनावी हार-जीत तो होती ही रहती है, काम आता है राजनीतिज्ञों का जुझारूपन। वायनाड से चुनाव जीतने के बाद प्रियंका सांसद के रूप में बेहतरीन भूमिका निभा रही हैं। प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गएथे। राजनीति में सवालों का सिलसिला चलता रहता है लेकिन प्रियंका सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है। कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसका फैसला तो पार्टी को ही करना है। कांग्रेस को ओवरहालिंग की जरूरत है।

उड़ान कंपनियों से सख्ती से निपटे सरकार

जो बाजार दो कंपनियों के अधिकार या एकाधिकार में बदल जाता है, वहां उपभोक्ता के संप्रभु भागीदार होने का दर्जा छिन जाता है और वह आपूर्ति पाने वाले में बदल जाता है और इस तरह अपनी गरिमा और चुनने के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऐसे में उसके हिस्से में जो भी आता है, वह उसे लेने को मजबूर होता है। हवाई यात्रा में खुले चुनाव का भ्रम तो उसी दिन हवा हो गया था, जब राष्ट्रीय उड्डयन की शर्तें दो बड़े खिलाड़ी तय करने लगे थे, जब निजी वर्चस्व सार्वजनिक प्राधिकार की आभा धूमिल करता है, तब राज्य का दायरा सिकुड़ने लगता है। पिछले सप्ताह भारत के नागरिक उड्डयन के परिदृश्य में यही देखने को मिला, जब एक एयरलाइन द्वारा ऑपरेशन की क्षमता ध्वस्त होते ही पूरा देश विभ्रम, उथल-पुथल और शोषण में गर्क हो गया। देश के विमानन क्षेत्र में 63 फीसदी की चौंकाने वाली हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो अपने ऑपरेशंस को लापरवाही के हद तक ले गई। नतीजतन, तीन दिन में उसको 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और 10 लाख से अधिक यात्रियों के लिए जीवन जैसे एकाएक ठहर गया- शादियां रुक गईं, अतिथिगण गंतव्य तक नहीं पहुंच सके और असंख्य परिवार अधर में लटक गए। हवाई अड्डे देखते-देखते भारी थकावट और असहनीय क्षोभ के केंद्र बन गये। जब पूरा देश उबल उठा, तब सरकार ने प्रतिक्रिया दिखाई। दोषी उड्डयन दिग्गज से जवाबदेही मांगने के बजाय सरकार ने पायलटों को आराम देने से संबंधित अपने 18 महीने पुराने नियमों को फौरी तौर पर वापस ले लिया। रेगुलेशन से जुड़े निर्णायक कदम उठाने का समय राजनीतिक रूप से कदम खींचने का उदाहरण बन गया जिससे यह संदेश गया कि ताकतवर सरकार ने एयरलाइन के अधिकार और उसकी आक्रामकता के आगे समर्पण कर दिया है। इसका नतीजा सिर्फ असुविधाजनक नहीं, बल्कि डरावना रहा। सिंगापुर के उत्सुक अपने एक कर्मचारी की शादी में शामिल नहीं हो सके। उड़ानों के लगातार रद्द होने के बीच एक नये-नवेले जोड़े ने अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन हिस्सेदारी की और इन असुविधाओं के बदले उस एयरलाइन ने क्या दिया उसने कॉरपोरेट शब्दावली में सिर्फ बहाने बनाये। उसने तकनीकी परेशानियों, मौसम संबंधी दिक्कतों, हवाई अड्डों की भीड़ और एफडीटीएल-यानी पायलटों के आराम संबंधी नये नियमों को दोष दिया, जबकि एफडीटीएल नियम स्थगित नहीं तय हुआ था, इसका फैसला महीनों पहले लिया गया था। एयरलाइंस के पास पायलटों और क्रू की नियुक्तियों के लिए और रोस्टर की नयी व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकार को अपनी इच्छा के मुताबिक चालित करने के बारे में सोचा और इसमें कामयाब रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री की प्रतिक्रिया ने इस बीमारी के बारे में ही बताया। हवाई अड्डों पर व्याप्त अराजकता पर जब लोगों का गुस्सा भड़का, तब भी वह निष्क्रिय थे। जब संसद में इस पर सवाल उठे, तब वह सामने आये।वह इंडिगो को मामूली चेतावनी देते, निष्फल बैठकें करते और प्रतीकात्मक निरीक्षण करते दिखे। सरकार द्वारा पायलटों के आराम के लिए बनाये गये अपने ही नियम से पीछे हटना शक्तिहीनता और कॉरपोरेट दबाव के आगे झुकने का स्पष्ट उदाहरण था। इस बीच एयर इंडिया की कमजोरी भी सामने आई। सुस्ती, पुराने पड़ चुके विमान और अपनी आंतरिक दुर्बलता के लिए कुख्यात एयर इंडिया ने भी इस दौरान अपनी उड़ानें रद्द कीं। विपक्ष ने यह मौका लपका और सरकार से कुछ असुविधाजनक सवाल पूछे। उसने केंद्र की भाजपा सरकार को उड्डयन क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति पैदा करने का जिम्मेदार बताया। अलबत्ता मौजूदा संकट को देश की उड्डयन क्षमता की कमी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक अरब चालीस करोड़ के देश में बमुश्किल आधा दर्जन एयरलाइंस हैं। कुल 839 रजिस्टर्ड विमानों में से 680 ही सक्रिय हैं। इनमें से आधे से अधिक का स्वामित्व इंडिगो के पास है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि घरेलू यात्रियों का आंकड़ा 2019 के 14 करोड़ से बढ़कर 2025 में 40 करोड़ हो चुका है। भारत को सालाना जितने पायलटों की जरूरत है, देश उसके आधे से भी कम पैदा करता है। ऐसे में पायलटों का संकट तो एफडीटीएल के शुरू होने के पहले से ही था। इस संकट के लिए डीजीसीए भी उतना ही जिम्मेदार है। उसके द्वारा जारी सलाहों को एयरलाइंस खारिज करती आई है। उड़ानें रद्द हो जाती हैं और यात्रियों के लिए भरपाई की व्यवस्था नहीं होती। बिना समीक्षा के ही किराये बढ़ जाते हैं और रिफंड कभी समय पर नहीं मिलता। एयरलाइंस निडर हैं, क्योंकि डीजीसीए उनके बचाव में खड़ा रहता है। रेगुलेटर यानी विनियामक की इस विफलता की मानवीय कीमत बहुत अधिक है। हवाई अड्डों पर फंसे असहाय यात्रियों को महज आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। इसे परीक्षा देने से वंचित रह गये छात्रों की पीड़ा, मजदूरी से वंचित रह गये श्रमिकों के दर्द, समय पर इलाज न करा पाये मरीजों की व्यथा, और परिवार के बीच उपस्थित न हो सकने वाले माता-पिताओं के कष्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। दुखद यह भी है कि कम वेतन पाने वाले और अपने नियोक्ताओं की मदद से वंचित हवाई अड्डों के कर्मचारीगण मुसाफिरों के गुस्से का निशाना बने। भारत इस जोखिम भरे रास्ते पर यात्रा जारी नहीं रख सकता। नागरिक उड्डयन विलासिता से अब आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक गतिशीलता और राष्ट्रीय एकीकरण की जीवनरेखा बन चुका है। लिहाजा, इसे आवश्यक ढांचागत प्रणाली के बजाय आकस्मिक व्यावसायिक क्षेत्र समझना तबाही को न्योता देना होगा। एक स्वायत्त उड्डयन प्राधिकरण का गठन भी समय की मांग है, जिसके पास जांच करने की स्वायत्तता, वित्तीय स्वतंत्रता और दंडित करने की क्षमता हो। विमानों के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करना और पायलटों के प्रशिक्षण को गति देने की आवश्यकता है। और सर्वोपरि, सरकार को सख्ती दिखानी होगी। एक अरब चालीस करोड़ की आबादी वाला देश उन दो निजी उड्डयन कंपनियों का बंधक नहीं बन सकता, जिन्हें संकट के समय मुनाफा कमाने में महारत हासिल है। भारत के आसमान को कॉरपोरेट के सामने समर्पण की निशानी बनने नहीं दिया जा सकता। देश को स्पष्टता, साहस और दृढ़ विश्वास का परिचय देना होगा, अन्यथा उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन ताकतों द्वारा ध्वस्त होते देखना होगा, जिन पर इन्हें रफ्तार देने की जिम्मेदारी थी।

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे!

एक पुरानी कहावत है कि जिस इमारत की नींव गहरी, बहुत ठोस और बहुत मजबूत होती है, वह इमारत झंझावातों की फिक्र नहीं करती। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत-रूस की सदाबहार दोस्ती के संदर्भ में इस कहावत को फिर याद दिला दी है। दोनों की मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोस्ती नई चुनौतियों के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ पुतिन ने कहा कि भारत को हर हाल में रूस ईंधन की निर्बाध आपूर्ति करता रहेगा। दोनों का संदेश सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए है। डोनाल्ड ट्रम्प पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इस पर भारत ने जब कहा कि हम अपनी जरूरतों के अनुरूप निर्णय लेते हैं तो ट्रम्प ने अपने बयान में यह जोड़ दिया कि तेल खरीदना बंद करने में भारत को कुछ वक्त लग सकता है। रूस से तेल खरीदने के कारण ही भारत पर ट्रम्प ने 25 प्रतिशत टैरिफ का जुर्माना लगाया हुआ है। कुछ लोग यह सोचने लगे होंगे कि क्या जुर्माने के दबाव में भारत झुक जाएगा और क्या रूस से दोस्ती में कुछ कमी आ सकती है कई लोगों ने मुझसे यह बात पूछी भी थी। मैंने हमेशा यही कहा कि हिंदुस्तान न पहले झुका था, न आज झुका है और न कल झुकेगा। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन किसी के आगे नहीं झुकते। हम केवल वहीं झुकते हैं, जहां श्रद्धा होती है। भारत और सोवियत यूनियन (अब रूस) के रिश्ते किसी आर्थिक वजह से नहीं बने हैं। दिलों के रिश्ते मैत्री, सद्भाव, आचार-विचार की समानता और सांस्कृतिक कारणों से बने हैं। भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री आए जो विचारों से अमेरिका के नजदीक थे लेकिन उन्होंने जब फाइलों के माध्यम से गहराई से जानकारी ली तो उन्होंने भी रूस के साथ दोस्ती बरकरार रखी। दोस्ती दरअसल दोनों देशों के दिलों के बीच है. जब मैं वर्ल्डकप फुटबॉल देखने के लिए मास्को गया तब पहली बार मैंने महसूस किया कि भारतीयों के प्रति रूस के लोगों के मन में कितना स्वाभाविक प्रेम और सम्मान है। उसके पहले संसद के सेंट्रल हॉल में मि. पुतिन से मैं मिल चुका था। मास्को में फुटबॉल मैच के दौरान हाथों में तिरंगा लिए मैंने जब हिंदुस्तान और रूस जिंदाबाद के नारे लगाए तो नीचे बैठे पुतिन हाथ हिलाते हुए मुस्कुराए। मैं पाठकों को बता दूं कि सोवियत यूनियन भले ही साम्यवादी विचारधारा का देश रहा और रूस का रुख भी वही रहा लेकिन क्रेमलिन में आप उनका ऑफिस देखेंगे तो उसकी भव्यता अमेरिका और चीन के कार्यालयों से भी बेहतर है, वहां सोने की परतें लगी हुई हैं। शायद वे साम्यवाद के माध्यम से अपनी जनता के जीवन में भव्यता लाना चाहते होंगे, मगर अब केवल नाम का ही साम्यवाद बचा है। नई पीढ़ी के पाठकों के लिए यह जानकारी मैं साझा करना चाहता हूं कि भारत को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी लेकिन गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल अपना शासन छोड़ने को तैयार नहीं था। दिसंबर 1961 में हमारी फौज ने हमला किया और गोवा को आजाद करा लिया। उस वक्त यूरोप से लेकर अमेरिका तक हमारे विरुद्ध थे लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। यूनाइटेड नेशन में उसने हमारे पक्ष में वीटो किया था। 1971 में पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया ताकि भारत को धमकाया जा सके लेकिन सोवियत संघ की पनडुब्बियां वहां पहले ही पहुंच चुकी थीं।

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

ललित गर्ग ।

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सोचने की क्षमता खो चुके हैं क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झुलसने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी है। गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है क्या वहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता छलती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं। नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर। गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यावसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है। हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान-माल को ही क्षति नहीं पहुंचाती, बल्कि देश की बदनामी भी कराती है। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

एग्री बिज़नेस समिट 2025–तकनीक, कानून और सहकारिता से बदलेगी कृषि की तस्वीर

नई दिल्ली।(साहिल गौड़) PHD-CCI द्वारा ताज पैलेस होटल में आयोजित एग्री बिज़नेस समिट 2025 में देशभर के मंत्री, न्यायविद, सहकारी संस्थाओं के दिग्गज, कृषि विशेषज्ञ और नीति-निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर विस्तृत चर्चा की।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकनीक-आधारित, किसान-केंद्रित कृषि मॉडल का विज़न साझा किया, जबकि IFFCO चेयरमैन दिलीप भाई संघानी ने सहकारिता और गुणवत्तापूर्ण इनपुट्स की भूमिका पर जोर दिया। NAFED निदेशक अशोक ठाकुर ने खरीद और बाजार-सुधार पर सुझाव रखे।

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और डॉ. सुधीर कुमार जैन ने कृषि-नवाचार, किसान अधिकारों और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मजबूत कानूनी ढाँचे की आवश्यकता बताई।

वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल मित्तल ने कृषि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ AI की भूमिका–फसल निगरानी, विवाद समाधान, सप्लाई-चेन अनुकूलन–पर विस्तृत विचार रखे।

अर्थशास्त्री डॉ. राम गोपाल अग्रवाल, विशेषज्ञ रमेश चंद, वरिष्ठ नेता श्याम जाजू और कई अन्य वक्ताओं ने उत्पादकता, आर्थिक सुधार और सहकारिता आधारित विकास मॉडल को कृषि उत्थान की कुंजी बताया।

AI आधारित चेतावनी प्रणाली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल भुगतान और ई-मार्केटिंग पर विशेष फोकस रहा। समिट ने स्पष्ट किया कि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार, न्यायपालिका, उद्योग, सहकारिता और विज्ञान–सभी का संयुक्त प्रयास जरूरी है।

25वाँ श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 9 से 15 दिसंबर तक

हनुमान वाटिका पार्क, दिलसुखा गार्डन में आध्यात्मिक माहौल

नई दिल्ली।(आकाश शरण) दिलसुखा गार्डन, दिल्ली-95 के हनुमान वाटिका पार्क में इस वर्ष 25वाँ विशाल श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कथा का शुभारंभ 9 दिसंबर की सुबह 11 बजे मंगल कलश यात्रा के साथ होगा।

महोत्सव में ब्रह्मलीन आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी कथा का वाचन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भागवत परिवार समिति (रजि.) द्वारा किया जा रहा है।

विशेष उत्सव

12 दिसंबर 2025- श्रीकृष्ण जन्म एवं श्री कृष्ण पूजन

13 दिसंबर 2025- श्री गोवर्धन पूजन एवं छप्पन भोग

14 दिसंबर 2025- रुक्मणी-माधव विवाह

15 दिसंबर 2025- सुदामा चरित एवं फूल बंगला दर्शन

कथा में मुख्य यजमान श्री मनीष श्याम लला एवं श्री कसुम पाल सिंह राठौर होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भक्तों को आध्यात्मिक शांति, संस्कार एवं सामाजिक सद्भाव का संदेश देना है।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल-Vrajras Productions- पर भी उपलब्ध रहेगा।

आयोजक समिति ने सभी भक्तों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ लेने की अपील की है।

राजेंद्र चिंतन समिति ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 141 वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया

नई दिल्ली, इंद्रजीत सिंह) राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष समारोह राजेंद्र चिंतन समिति और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा संयुक्त रूप से संसद भवन के पास स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके महान योगदान और सादगीपूर्ण जीवन को याद किया।

कार्यक्रम में दिल्ली विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने दीप प्रज्जवलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ राजेंद्र चिंतन समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी, संयोजक पंकज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा, श्रीमती देवयानी शर्मा, श्रीमती मोनिका शर्मा भी मौजूद थे।

इस मौके पर डॉ योगानंद शास्त्री ने वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवियों को राजेंद्र प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया। जिनमें प्रमुख रमेशचंद शर्मा, विवेक शुक्ला, सुनील नेगी, संजीव शर्मा, कोड्ले चत्रप्पा, राहुल शर्मा, मनोज शर्मा, अनुराग जोशी, मुश्ताक अंसारी, मानसी शर्मा, जितेंद्र, खुज्ञान सिंह, संजय शर्मा, राखी अरोड़ा, शिवानी, बी एम गुप्ता, अनिकेत, मोनिका शर्मा, देवयानी थे।

दिल्ली विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जीवन सत्य, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का प्रेरणास्रोत है। उनके नेतृत्व ने भारत को न केवल संविधान दिया, बल्कि एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव भी प्रदान की। उनके विचार आज भी हमारे देश को नई दिशा देने में सहायक हैं।÷ उन्होंने कहा उनका त्याग, निष्ठा और देशसेवा हमें हर दिन बेहतर भारत निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

राजेंद्र चिंतन समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे सादगी और अनुशासन के साथ बड़ा कार्य किया जा सकता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व भारत के इतिहास में दुर्लभ हैं। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।÷ उन्होंने कहा, ÷डा. राजेन्द्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और आजीवन निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे। आज हम उनके दिखाये गये रास्ते पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजली अर्पित कर सकते हैं।÷

राजेंद्र चिंतन समिति के संयोजक पंकज शर्मा ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन से यह सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए।÷

राजेंद्र चिंतन समिति की संयोजिका देवयानी एवं मोनिका शर्मा ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मैं उनके अद्भुत नेतृत्व, सादगी और सेवा भावना को नमन करती हूँ। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर भारत को सशक्त बनाना चाहिए।÷

समारोह में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी भाग लिया। उपस्थित जनसमुदाय ने राष्ट्र के प्रति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। राजेंद्र चिंतन समिति और नई दिल्ली नगर परिषद ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समारोह ने देशवासियों को डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया। इस मौके पर राजेंद्र चिंतन समिति के संयोजक पंकज शर्मा, मोनिका शर्मा और श्रीमति देवयानी ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

भस्म और रुद्राक्ष धारण करने से मान-सम्मान और ऐश्वर्य की होती है प्राप्ति - कथावाचक प्रद्युम्न कृष्ण

पिंजरापोल गौशाला मे आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के दुसरे दिन कथावाचक ने बेल पत्र के महत्व, भस्म धारण करने व रुद्राक्ष की महिमा का कराया रसपान

कुशीनगर।(शिव कैलाश परिवार के तत्वावधान मे पडरौना नगर के पिंजरापोल गौशाला प्रांगण आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के दुसरे दिन बुधवार को वृंदावन से पधारे कथावाचक ने बेल पत्र के महत्व, भस्म धारण करने व रुद्राक्ष की महिमा का रसपान कराया। कथावाचक प्रद्युम्न कृष्ण महाराज ने बताया कि बेलपत्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ है, जो सभी पापों का नाश कर, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं ये भगवान शिव को प्रिय हैं और इन्हें लगाने से व्यक्ति शिवलोक प्राप्त करता है, साथ ही सांसारिक सुख, धन और आरोग्य भी मिलता है, और भूत-प्रेत जैसी बाधाएं दूर होती हैं, जिससे व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। उन्होंने कहा कि बेलपत्र से पूजा करने पर सभी पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। बेलपत्र के तीन पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र की जड़ के पास दीपक जलाने या भोजन कराने से दरिद्रता दूर होती है और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। कथावाचक ने कहा कि भस्म शिव का स्वरूप है और इसे लगाना शिवभक्त की पहचान है। ललाट पर भस्म लगाने से सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति शिव का प्रिय हो जाता है। उन्होंने रुद्राक्ष के महत्व बताते हुए कहा कि रुद्राक्ष भगवान शिव का अंश है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे धारण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। रुद्राक्ष धारी के पास से भूत-प्रेत, डाकिनी-शाकिनी आदि दूर भागते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को समाज में मान-सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। संस्था के सदस्य कुलदीप, पीयूष, बिक्की, विजय, अमन, मनीष गोयल, शिवशंकर, पिंजरापोल गौशाला के मंत्री अखिलेश गोयल,प्रदीप गोयल, ओमप्रकाश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

भारत तिब्बत संवाद मंच द्वारा साझा विरासत एवं साझा भविष्य विषय पर गोष्ठी आयोजित

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के नोबल शांति पुर्वस्कार प्राप्त करने के 36 वीं वर्षगांठ मनाई गई

कसया, कुशीनगर। भारत तिब्बत संवाद मंच द्वारा तिब्बती मंदिर कुशीनगर के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के नोबल शांति पूरस्कार प्राप्त करने के 36 वीं वर्षगांठ पर भारत तिब्बत संबंध - साझा विरासत एवं साझा भविष्य विषय पर गोष्ठी आयोजित हुई। बुधवार को आयोजित गोष्ठी में राष्ट्रीय समन्वयक भारत तिब्बत समन्वय केंद्र तासी दिकी ने चीन द्वारा तिब्बत के उत्पीड़न का मार्मिक वर्णन किया।

कहा कि तिब्बत के लोग चीन के दमन से अपना जीवन कष्ट में जी रहे हैं। प्रकृति संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। तिब्बत की धर्म, भाषा, संस्कृति को मिटाने का काम कर रहा है। तिब्बत की आजादी के लिए जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। संयोजक पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि भारत और तिब्बत संबंध और चीन की कड़ी को लेकर स्पष्ट संदेश युवाओं के बीच जाना चाहिए। चीन की अराजकता, सैन्य शक्ति से तबाह तिब्बत को बचाने के लिए भारत पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। विषय प्रवर्तन करते हुए संयोजक डॉ शुभलाल ने करते हुए कहा कि भारत एक जीवंत राष्ट्र है। तिब्बत की आजादी हमारी आजादी है। पर्यावरण संतुलन चीन बिगाड़ रहा है। सरकार दलाई लामा को दोनों सदन में संबोधित करने का अवसर दें। भारत रत्न दें। अध्यक्षता करते हुए बुद्धा पीजी कालेज के प्राचार्य प्रो विनोद मोहन मिश्रा ने कहा कि तिब्बत और भारत के संबंध पुराने समय से प्रगाढ़ रहे हैं। तिब्बती मंदिर के प्रबंधक कंचुक लामा ने तासी को सम्मानित किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से तिब्बती को चीनी बनाना विषय को दर्शाया गया।

संचालन दिवाकर मणि ने किया इस दौरान भंते आलोक, तिब्बत से मिग्मार, भंते वाइजर, सोनम श्रृंग लामा, डॉ निगम मौर्य, डॉ बीना गुप्ता, संतोष दत्त राय, कैप्टन वेद प्रकाश मिश्रा, सुरेश गुप्ता, सभासद केशव सिंह, प्रधान डॉ संजय यादव, सभासद प्रभुनाथ सिंह, अनिल कुमार मल्ल, राजेश सिंह, अमोद कुमार सिंह, बैजनाथ, एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे।

लाल किला विस्फोट : धमाके के बाद घट गई पर्यटकों की संख्या, आसपास के बड़े बाजारों में ग्राहकों की आमद पर असर

नई दिल्ली। लाल किला के पास फिदायीन हमले के एक माह बाद धमाके के जख्म आज भी पर्यटकों की जेहन में ताजा है। इस बात की तस्दीक सैलानियों की संख्या में आई कमी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुमानित आंकड़े भी कर रहे हैं। पहले लाल किला देखने के लिए रोजाना सात से आठ हजार पर्यटक आते थे लेकिन अब यह संख्या घट गई है। टूर एंड ट्रैवल एजेंटों का दावा है कि दिल्ली भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटक पहले लाल किला को अपनी 10 सबसे मनपसंदीदा लिस्ट में में रखते थे लेकिन धमाके के बाद ट्रेंड बदल गया है। विदेशी पर्यटक अब लाल किला जाने से कतरा रहे हैं। इसकी जगह वह दिल्ली के अन्य ऐतिहासिक इमारतों का रुख कर रहे हैं। इसमें कुतुब मीनार उनकी पहली पसंद है। ट्रैवल एजेंट रमेश कुमार ने बताया कि बीते नवंबर माह में उनके पास 25 फीसदी विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आया है, जो दिल्ली आ भी रहे हैं, तो कई पर्यटक लाल किला नहीं जा रहे हैं। हालांकि, कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं, जो अभी भी लाल किला जाना चा रहे हैं। लेकिन, इनकी संख्या कम है।

साल 2024-25 में स्वदेशी पर्यटक की संख्या 28,84,399 लाख रही

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, साल 2024-25 में लाल किला का दीदार करने वाले स्वदेशी पर्यटक की संख्या 28,84,399 लाख रही है। ऐसे में देश के टॉप 10 पर्यटक स्थलों में चौथे स्थान के साथ 5.32 फीसदी भागीदारी रही। विदेशी पर्यटकों की 79, 311 हजार रही है। देश के टॉप 10 पर्यटक स्थलों में नौवें स्थान के साथ 3.28 फीसदी भागीदारी रही।

स्कूलों ने भी बनाई दूरी

लाल किला के पास स्थानीय दुकानदार और गाइड सबसे ज्यादा परेशान हैं लाल किले के सामने चांदनी चौक में चाय-नाश्ते की दुकान चलाने वाले राजू कहते हैं कि ग्राहक 30 प्रतिशत कम हो गए। पहले दिन के 8-10 हजार रुपये होते थे, अब 2 हजार भी मुश्किल से। कई स्कूलों ने भी दिल्ली टूर से लालकिला हटा दिया है। ऑटो और ई-रिक्शा वाले भी परेशान हैं। मंगलवार को लखनऊ से इंडिया गेट पर आए एक परिवार ने बताया कि बच्चे लाल किला देखना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया। खबरों में देखा कि जहां बम ब्लास्ट हुआ था, अब मन नहीं करता।

मोदी जी के डंडे का खौफ है..सुरक्षा तो है, पर ग्राहक नहीं

मोदी जी के डंडे का खौफ है मैडम... सरकार आतंकवादियों के नाक में नकेल तो कस रही है लेकिन शादी के सीजन में इन कलमुंहे आतंकियों ने रोजगार पर लात मार दी। बाहरी ग्राहक छिन गए। स्थानीय ग्राहक तो रोजाना आते थे और अब भी आ रहे हैं। यह बातें राजकुमार ने बताई, जिनकी दुकान लाल किले की ठीक सामने चांदनी चौक में है। लगभग चार हफ्ते पहले, 10 नवंबर को लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने पुरानी दिल्ली के बाजारों की रौनक को एक झटके में बदल दिया। उस हादसे में दर्जनों लोग मरे और घायल हुए, विस्फोट की आवाज और भय ने करीब-करीब हर दुकानदार और ग्राहक को हिला कर रख दिया।

बोले दुकानदार...

दुकान तो हमने खोले ही रखी, लेकिन बाहरी ग्राहकों का आना बंद हो गया था। शादी का सीजन चल रहा है।

दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर किया घोषित

नई दिल्ली।

■ मोदी बोले- दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा; कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में

यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। ये फैसला उस समय आया है, जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटैन्जिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। यह 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, भारत और दुनियाभर के लोग उत्साहित हैं। हमारे लिए दिवाली, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें। यूनेस्को की यह लिस्ट दुनिया की ऐसी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजों को शामिल करती है, जिन्हें छू नहीं सकते लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसे अमूर्त विश्व धरोहर भी कहते हैं। इसका मकसद है कि ये सांस्कृतिक धरोहरें सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें। फिलहाल, भारत की 15 धरोहरें पहले से अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में जगह बना चुकी हैं। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छऊ नृत्य भी शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग को 'वोट चोरी करने' का हथियार बना रही है भाजपा : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचन आयोग को ''वोट चोरी करने'' का हथियार बना रही है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''भारत की जनता ये तीन बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। प्रधान न्यायाधीश को निर्वाचन आयोग से संबंधित चयन समिति से क्यों हटाया? 2024 चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग को लगभग पूरी कानूनी सुरक्षा क्यों दी? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों?'' उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब एक ही है कि निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का औज़ार बनाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी 'वोट चोरी' के कृत्य को अंजाम देकर 'आइडिया ऑफ इंडिया' (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रही है। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान 2023 के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में ''पूर्वव्यापी प्रभाव'' से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कठघरे में लिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि 2023 के इस कानून को बदलने की जरूरत है क्योंकि यह निर्वाचन आयुक्तों को ''यह ताकत देता है कि वे जो चाहें करें''। उन्होंने कहा था कि इसकी चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

कांग्रेस चोरों का सरदार - निशिकांत दुबे

नई दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस को चोरों का सरदार करार देते हुए चुनावी सुधारों पर चल रही बहस के दौरान पार्टी की तीखी आलोचना की। एएनआई से बात करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस चोरों का सरदार है, और कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता। अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं? उन्हें सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक में दिलचस्पी है। यही कारण है कि वे एसआईआर और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं।

ईवीएम नहीं, दिलों को हैक करते हैं पीएम मोदी - कंगना रनौत

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत संसद कांग्रेस के ईवीएम हैक वाले आरोप को लेकर बड़ा आरोप लगाया। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस वालों तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते प्रधानमंत्री, वो तो दिलों को हैक करते है। दरअसल, फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान बोल रहीं थी। इस दौरान उन्होंने में एसआईआर पर बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ईवीएम नहीं बल्कि दिल हैक करते हैं। कंगना रनौत का कहना है कि विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और हर तरह की चालें चलीं। उल्लेखनीय है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने एसआईआर, वोट चोरी और वंदे मातरम के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी के जवाब के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बीजेपी पर तीखा व्यंग किया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं उनके (राहुल गांधी) के दौरे की कोई खबर नहीं रखती हूं, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं। उनकी खबरें हमेशा बेकार ही होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चरित्र में कोई ताकत नहीं है इसलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा ने निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा है। एक तरफ जहां, सत्ताधारी बीजेपी ने उन पर बार-बार विदेश यात्राओं के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तो वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का हवाला दिया है।

प्रधानमंत्री आधा समय विदेश में बिताते हैं, फिर राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल क्यों : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के प्रस्तावित जर्मनी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना आधा कामकाजी समय विदेश में बिताते हैं तो फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वह भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 'एलओपी यानी 'लीडर ऑफ पर्यटन हैं।

राहुल गांधी पर जगदंबिका पाल ने साधा निशाना, कहा- जनता को गुमराह करने की कर रहे कोशिश

नई दिल्ली।

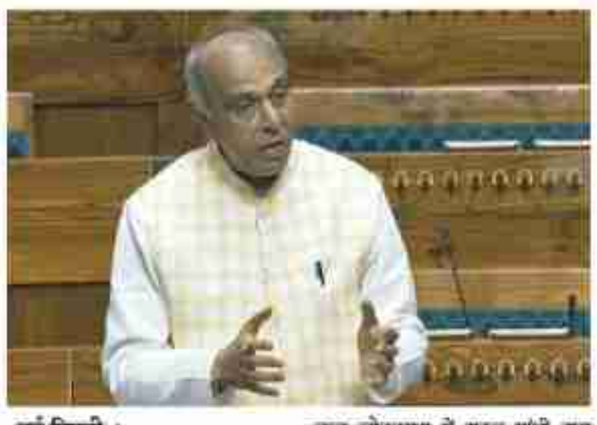

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग (ईसीआई) पर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए पाल ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के बयान सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे चुनाव आयोग के खिलाफ बयान सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए दे रहे हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि कल लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाना पहली बार नहीं था।

वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एसआईआर के मुद्दे पर इन लोगों ने चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना दिया था। उस समय चुनाव आयोग ने उन्हें और उनके 30 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। भारत के चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप लगाने वाले गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सुझाव दिया कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि वह (राहुल गांधी) आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए तो वे इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए, उन्हें ईवीएम और चुनाव आयोग को इसी तरह दोषारोपण करते रहने दें और अपने भीतर न झांकें - इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद राम गोपाल यादव ने बुधवार को कहा कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास में गड़बड़ी करने वाला असली दोषी जिला स्तर पर है। एसपी सांसद ने तर्क दिया कि चुनाव सुधारों के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और उन्होंने व्यापक सुधारों की वकालत की। यादव ने कहा, चुनावी सुधारों के लिए कुछ चीजें अनिवार्य हैं : चुनाव आयोग की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि हम चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वे किसी जीवित व्यक्ति को मृत या मृत व्यक्ति को जीवित दिखा दें। व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

इंडिगो संकट पर डीजीसीए सख्त, सीईओ पीटर एल्बर्स फिर हुए तलब; कहा- पेश करें ये डेटा

नई दिल्ली।

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ को गुरुवार को दोपहर 3 बजे हालिया परिचालन बाधाओं से जुड़ा व्यापक डेटा और अपडेट पेश करने का निर्देश दिया है। इंडिगो संकट के 9वें दिन बुधवार को भी बंगलूरू एयरपोर्ट से 61 उड़ानें रद्द कर दी गईं, इसमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान वाली उड़ानें थी। यह खबर तब सामने आई जब इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कल यानी नौ दिसंबर को दावा किया था कि एयरलाइन की स्थिति अब सामान्य हो गई है। डीजीसीए ने कहा कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। नियामक के आदेश के अनुसार, एयरलाइन को उड़ानें बहाल करने, पायलटों और चालक दल की भर्ती योजना, पायलट और केबिन क्रू की संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या और अब तक जारी किए गए रिफंड आदि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60फीसदी से भी अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इस एयरलाइन का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपये तक घट चुका है। ऐसे में एयरलाइन की स्थिति सामान्य होने के दावों के बीच भी उड़ानें रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा है।

सरकार की सख्त कार्रवाई

लगातार जारी गड़बड़ी के बीच अब बीते दिनों से सरकार भी सख्त होती नजर आ रही है। इसके तहत पहले तो डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को शो-कॉज नोटिस भेजा। उसके बाद एयरलाइंस के किराए पर कैप लगाया गया ताकि टिकट महंगे न हों।

इसी क्रम में मंगलवार को सरकार ने इंडिगो की विंटर फ्लाइट शेड्यूल में 10फीसदी कटौती का आदेश दिया। इससे रोज लगभग 220 उड़ानें कम होंगी। मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि यह कदम इसलिए जरूरी था ताकि इंडिगो का संचालन स्थिर हो सके और रद्द उड़ानों की संख्या कम हो।

22 दिसंबर को अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को घोषणा की कि वह 22 दिसंबर को एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। कबीर ने घोषणा की कि उनका इरादा आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को सीधे चुनौती देने का है। एएनआई से बात करते हुए कबीर ने कहा कि मैं 22 दिसंबर को एक नई पार्टी की घोषणा करूंगा। मैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारूंगा।

हरियाणा में शहरी विकास कार्यों को मिलेगी गति

चंडीगढ़।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से 1700 करोड़ रुपये की राशि की जारी
*शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में आएगी तेजी

हरियाणा सरकार द्वारा शहरी विकास को सुदृढ़ करने और राज्य की प्रमुख शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचा सुधार को गति देने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में शहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।

यूपी में घुसपैठियों का खेल खत्म! योगी सरकार बना रही बायोमेट्रिक प्रोफाइल और निगेटिव लिस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों सहित घुसपैठियों की पहचान करने, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर उनकी प्रोफाइल (हाईटेक प्रोफाइल) बनाने और बाद में उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों के दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए एक विस्तृत 'बायोमेट्रिक डेटाबेस और देश भर में एक नकारात्मक सूची बनाने का प्रस्ताव है।

एडवांस्ड डॉक्यूमेंट-स्कैनिंग सिस्टम का होगा इस्तेमाल

अधिकारी ने को बताया कि प्रस्तावित कार्य योजना पर अभी काम किया जा रहा है। उसके तहत पहचान के दावों को सत्यापित करने और यह पता लगाने के लिए कि संदिग्ध घुसपैठिये राज्य में कितने समय से रह रहे हैं, उनके चेहरे की पहचान, 'फिंगरप्रिंट मैपिंग और 'एडवांस्ड डॉक्यूमेंट-स्कैनिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, ''व्यापक सत्यापन अभियान के तहत देश में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों की एक पूरी प्रोफाइल तैयार करने का विचार है। इसमें बायोमेट्रिक तथा सभी दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होगा।

सघन सत्यापन अभियान चला रही सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों समेत गैर-कानूनी तरीके से भारत में रह रहे लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी ने बताया कि सरकार गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे लोगों की एक नकारात्मक सूची बनाने का विचार कर रही है जिसे दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे लोग जाली पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में दोबारा दाखिल ना हो सकें।

जाली दस्तावेजों की होगी पहचान

अधिकारी ने कहा कि सभी संदिग्ध नकली पहचान कार्ड, जिसमें आधार से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं, को 'हाई-टेक स्कैनिंग और मौजूदा डेटाबेस के साथ सत्यापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि जाली दस्तावेजों की पहचान की जा सके और ऐसे दस्तावेज तैयार करने में शामिल नेटवर्क को खत्म किया जा सके। अधिकारी ने कहा, ''जरूरत सिर्फ अवैध घुसपैठियों की पहचान करने पर ही नहीं है, बल्कि उनकी जवाबदेही तय करने और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी है जो उन्हें जाली दस्तावेज दिलाने में मदद करते हैं।